जनवरी, 2023 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियों पर मासिक सारांश

1. स्वच्छ भारत मिशन

i. सभी 4,715 शहरों / कस्बों को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) घोषित किया गया है, जिनमें से 4,355 शहरों को तीसरे पक्ष के सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया गया है, 3,547 शहरों को ओडीएफ + के रूप में प्रमाणित किया गया है, 1191 शहरों को ओडीएफ + + और 14 शहरों (इंदौर, सूरत, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), तिरुपति, चंडीगढ़, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, हैदराबाद, ग्रेटर विशाखापट्टनम, कराड, पंचगनी, भोपाल, बारामती और मैसूर) को जल + के रूप में प्रमाणित किया गया है।

ii. 3,326 से अधिक शहरों में 67,407 शौचालयों को गूगल मानचित्र पर "एसबीएम शौचालय" के नाम से देखा जा सकता हैं।

iii. स्वच्छता ऐप महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा हैं, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतों के समाधान के लिए उन्हें ऐप में दर्ज करा सकते हैं, ताकि नगर निगम द्वारा उनका समाधान किया जा सके।स्वच्छता ऐप के कुल 2.08 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, जिन्होंने 2.55 करोड़ शिकायतें दर्ज की हैं, जिनमें से 2.39 करोड़ शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जो कुल शिकायतों का 94% से अधिक है।

iv. 01 अक्टूबर 2022 को जीएफसी 2022 का परिणाम स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह 2022 में घोषित किया गया था।कचरा मुक्त शहरों (जीएफसी) के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत 7-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या 1 है, 5-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या 11 है, 3-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या199 है और 1-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या 234 है।

v. दिनांक 20 जनवरी, 2023 को सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मिशन के प्रमुख न्यूजलेटर स्वच्छवार्ता का शुभारंभ किया गया।स्वच्छवार्ता का पहला संस्करण एसबीएम-यू 2.0 के पहले वर्ष के दौरान मिशन और मंत्रालय द्वारा की गई सभी प्रमुख गतिविधियों, अभियानों और पहलों का पुनर्मूल्यांकन करता है।

vi. 16वां भारत-फ्रांसीसी संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) 19 जनवरी, 2023 को आयोजित किया गया था और इसकी सह-अध्यक्षता सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और श्री इमैनुएल डी लैनवर्सिन, विशेष सचिव हाउसिंग, अर्बन एंड लेंडस्केप प्लानिंग, इकोलोजिकल ट्रांजिशन और टेरिटोरियल कोहेशन मिनिस्ट्री, फ्रांस सरकार द्वारा की गई थी।

vii. 21 दिसंबर और 30 जनवरी, 2023 के बीच एआईसीटीई के सहयोग से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ ट्यूलिप पहल पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और यूएलबी के लिए ऑनलाइन कार्योन्मुखी सत्र आयोजित किए गए थे।

II. स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम)

i. 181,348 करोड़ रुपये की 7821 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 1,00,151 करोड़ रुपये की 5,316 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं।जनवरी 2023 में, 6,622 करोड़ रुपये की 276 अतिरिक्त परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

ii. स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर, स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के तहत सभी 100 स्मार्ट शहरों में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों (आईसीसीसी) का संचालन किया गया था।आईसीसीसी शहर प्रबंधन में सुधार करेंगे, नगरपालिका सेवा प्रदायगी को एकीकृत करेंगे, स्थिति से संबंधित बेहतर जागरूकता पैदा करेंगे, शहरी सेवा प्रदायगी में दक्षता बढ़ाएंगे और समावेशी और स्थायी तरीके से डेटा-संचालित शासन सुनिश्चित करेंगे।

iii. सभी स्मार्ट शहरों में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर 'ओपन स्ट्रीट्स अभियान' शुरू किया गया था।ओपन स्ट्रीट्स अभियान एक बारंबार की जाने वाली गतिविधि है जिसका उद्देश्य सड़कों को सुरक्षित, बेहतर और अनुकूल सार्वजनिक स्थान के रूप में सृजित करने की पुनरकल्पना करना है, ताकि उन्हें खेलने,व्यायाम करने और दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ाने के स्थान के रूप में प्रयुक्त किया जा सके।

iv. एससीएम ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा शुरू की गई डेटा पहलों पर एक कार्यशाला आयोजित की है।नीति आयोग और यूनिसेफ के प्रतिनिधियों ने एमओएचयूए में भारतीय शहरी वेधशाला (आईयूओ) में आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।

v. पुणे स्मार्ट सिटी में अर्बन आउटकम फ्रेमवर्क 2022 (यूओएफ 2022) के लिए दूसरी ओरिएंटेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया था। श्री राहुल कपूर, निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन और श्री संजय कोल्टे, सीईओ, पुणे स्मार्ट सिटी ने कार्यशाला की अध्यक्षता की।सभी 100 स्मार्ट शहरों को इस एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। यूओएफ 2022 का उद्देश्य शहर के परिणामों के आधार पर एक क्रॉस-सेक्टोरल शहरी डेटा बैंक बनाना है।

vi. ईज ऑफ लिविंग सूचकांक के रूप में, एक नागरिक धारणा सर्वेक्षण किया जा रहा है (जिसमें ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के तहत 30% अंक होते हैं)।नागरिक धारणा सर्वेक्षण (सीपीएस) शहर प्रशासन के लिए नागरिकों की प्राथमिकताओं और उनके शहरों में

जीवन की गुणवत्ता के बारे में उनकी धारणा को समझने का एक अवसर है।ये इनपुट सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए सरकारी प्रशासन की सहायता कर सकते हैं।इस वर्ष, 264 भारतीय शहरों में सीपीएस आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कम से कम 2.1 मिलियन नागरिकों की धारणाओं से जुड़ना है।यह सर्वेक्षण, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से प्रशासित किया जा रहा है, 9 नवंबर 2022 से शुरू हुआ है और 23 दिसंबर 2022 तक जारी रहेगा।आमने-सामने साक्षात्कार वाले ऑफ़लाइन संस्करण ऑनलाइन सर्वेक्षण के साथ समानांतर रूप से चलेंगे।

vii. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने 16 नवंबर 2022 को नवाचार श्रेणी के तहत स्मार्ट सिटी मिशन "डेटास्मार्ट सिटीज: डेटा के माध्यम से शहरों को सशक्त बनाने" द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी डेटा पहल के लिए बार्सिलोना में स्मार्ट सिटी एक्सपो वर्ल्ड कांग्रेस-2022 में नवाचार के लिए वर्ल्ड स्मार्ट सिटी पुरस्कार जीते।"पुरस्कारों के लिए 10 श्रेणियों में 60 देशों से कुल 337 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।डेटास्मार्ट सिटी पहल एक मजबूत डेटा ईकोलोजिकल सिस्टम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे वर्ष 2019 में शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से साक्ष्य-आधारित निर्णय लिए जा सकेंगे।

III. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

i. सभी राज्यों के लिए 77,640 करोड़ रू. की राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) को अंतिम रूप दे दिया गया है। आज की तारीख तक, 82,247 करोड़ रू. की लागत वाली परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) को मंजूरी दी गई है। कुछ राज्यों ने अपने स्वीकृत एसएएपी से अधिक परियोजनाएं शुरू की हैं। ऐसे मामलों में बढ़ी हुई संपूर्ण राशि राज्यों/यूएलबी द्वारा वहन की जाएगी।34,821 करोड़ रू. की 4,750 परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है और 45,405 करोड़ रू. की 1,097 परियोजनाओं का कार्य चल रहा है।कुल मिलाकर, लगभग 67,944 करोड़ रू. की पूर्ण / चल रही अमृत परियोजनाओं का अर्थात लगभग 88% वास्तविक कार्य पूरा हो चुका है।

ii. अब तक, 25 चयनित शहरों में परियोजना कार्यान्वयन (पूर्ववर्ती जेएनएनयूआरएम की पात्र परियोजनाओं सहित), प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (ए एंड ओई), सुधार प्रोत्साहन, और अमृत शहरों' और 'स्थानीय क्षेत्र योजना (एलएपी) और नगर नियोजन योजनाओं (टीपीएस)' में 'जीआईएस आधारित मास्टर प्लान के निर्माण' पर उप-योजनाओं के तहत राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को 38,100 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

iii. अमृत 2.0 के लिए शीर्ष समिति की छठी बैठक 4 जनवरी 2023 को सचिव (एमओएचयूए) की अध्यक्षता में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आयोजित की गई थी।

IV. दीनदयाल अन्त्योदय योजना /राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई/एनयूएलएम)

i. 8,981 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाए गए हैं; 6,820 स्वयं सहायता समूहों को परिक्रामी निधि दी गई; 19,839 उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण और प्रमाण-पत्र दिए गए थे; 14,606 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को रोजगार दिया गया; 8,473 लाभार्थियों को व्यक्तिगत और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए ऋण की सहायता प्रदान की गई और एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत एसएचजी को 16,984 ऋण दिए गए।

V. प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)

i. पीएम पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि) के तहत 61,40,904 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 46,67,904 आवेदनों को संस्वीकृत किया गया है और 40,83,135 आवेदनों के लिए संवितरण किया जा चुका है।

ii. जनवरी, 2023 के दौरान मिशन के तहत कुल 28.537 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

VI. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)/सभी के लिए आवास (एचएफए)

i. मिशन की शुरूआत से लेकर अब तक, मिशन ने 1.23 करोड़ आवासों को स्वीकृति दी है, जिनमें से 108.01 लाख आवास निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 68.70 लाख आवासों को पूर्ण किया जा चुका है/सुपुर्द किया जा चुका है।

ii. जनवरी, 2023 के दौरान पीएमएवाई मिशन के तहत कुल 2563.75 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

VII. आवास

i. नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने रेरा के तहत नियमों को अधिसूचित किया है, नागालैंड में नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया चल रही है।

ii. 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (नियमित - 26, अंतरिम - 06) की स्थापना की है। लद्दाख, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल ने नियम अधिसूचित कर दिए हैं जबकि प्राधिकरण की स्थापना अभी की जानी है।

iii. 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण (नियमित -24, अंतरिम - 04) की स्थापना कर चुके हैं। (अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में स्थापना की प्रक्रिया चल रही है)

iv. 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विनियामक प्राधिकरण रेरा के प्रावधानों के तहत अपनी वेबसाइटों शुरू कर चुके हैं। (अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मणिपुर में प्रचालन की प्रक्रिया चल रही है) ।

v. अब तक, देश भर में भू-संपदा विनियामक प्राधिकरणों द्वारा 1,06,510 शिकायतों (माह के दौरान 82 शिकायतों सहित) का निपटारा किया गया है।

vi. रेरा के तहत, अब तक 99,362 परियोजनाएं और 71,545 एजेंटों को पंजीकृत किया गया है। माह के दौरान 100 परियोजनाएं और 31 एजेंटों को पंजीकृत किया गया है।

*****